भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2640
जिसका उत्तर मंगलवार, 09 दिसम्बर, 2014 को दिया जाना है

निवेशक अनुकूल नीतियां बनाना

2640. प्रो. के. वी. थॉमस:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में ऑटोमोबाइल निर्माताओं ने कराधान संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृति देने में देरी, अवसंरचनात्मक और सम्भार तंत्र बाधाओं सहित कई प्रकार की अड़चनों को उद्धृत किया है जिसके कारण भारत में सुचारू रूप से कारोबार करने में बड़ी रुकावटें आ रही हैं और सरकार से अपनी नीतियों को निवेशक और कारोबार अनुकूल बनाने का आग्रह किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री जी. एम. सिद्देश्वर)

(क) और (ख): सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (सिआम) तथा ऑटोमोटिव कंपोनेन्ट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एक्मा) प्रत्येक वर्ष बजट पूर्व ज्ञापन प्रस्तुत करते हैं जिस पर सरकार द्वारा वार्षिक बजट तैयार करने के दौरान विचार किया जाता है। सरकार को ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स से समय-समय पर अभ्यावेदन प्राप्त होते रहते हैं।

सरकार ने ऑटोमोबाइल उद्योगों के विकास के लिए अनेक पहल की हैं। वर्तमान में, ऑटोमोबाइल सेक्टर में 100% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति है। सरकार ने वाहनों पर उत्पाद शुल्क दरों में कटौती भी की है जिससे विगत कई महीनों में बिक्री बढ़ाने में सहायता मिली है। इसके अलावा, सरकार ने भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग की उच्च वृद्धि दर को बनाए रखने और भारतीय बाजार में आकर्षण कायम रखने तथा भारतीय कंपनियों की प्रतिस्पर्धात्मकता को और बढ़ाने के लिए एक दस वर्षीय ऑटोमोटिव मिशन प्लान (एएमपी) 2006-16 तैयार किया है। यह मिशन प्लान इस सेक्टर के लिए सरकारी नीति का महत्वपूर्ण आधार है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने इस सेक्टर को सुदृढ़ करने के लिए कुछ अन्य नई पहल भी की हैं, जैसे ऑटोमोटिव उपकर निधि से अनुसंधान और विकास परियोजनाओं का वित्तपोषण, होमोलोगेशन और टेस्टिंग के लिए विश्वस्तरीय अवसंरचना की स्थापना के लिए नैशनल ऑटोमोटिव रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट (नैट्रिप) का प्रारंभ, ऑटो अनुसंधान और विकास कुशलता के केन्द्र और सहयोगात्मक अनुसंधान और विकास की आवश्यकता को पूरा करने तथा नेट्रिप के कार्यकलापों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए एक शीर्ष समन्वयकारी निकाय के रूप में नेशनल ऑटोमोटिव बोर्ड (एनएबी) की स्थापना। सरकार ने देश की जैविक ईंधन पर निर्भरता को कम करते हुए आम लोगों को स्वच्छ परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए नैशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान (एनईएमएमपी) 2020 के तहत देश में इलेक्ट्रिक/हाइब्रिड परिवहन को बढ़ावा देने के लिए पहल भी की है। एनईएमएमपी 2020 में वर्ष 2020 के अंत तक 6-7 मिलियन हाइब्रिड/इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रयोग में लाने की परिकल्पना की गई है।

******